आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)

बृहस्पतिवार 24.12.2025 समय 1305

मुख्य समाचार :–

- इसरो ने अमरीका के ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया।
- राज्य मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस पर वैट की दर बीस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने को मंजूरी दी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की समस्या दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है।

इसरो

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन– इसरो ने अमरीका की एएसटी स्पेसमोबाइल द्वारा निर्मित ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। इसे आज सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।

ब्लूबर्ड ब्लॉक–2 का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेलुलर ब्रॉडबैंड को सीधे बिना किसी बदलाव के स्मार्टफोन तक पहुंचाना है, जिससे दूर–दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन–इसरो को एलवीएम3–एम 6 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रक्षेपण ने अमरीका के अगली पीढ़ी के ब्लू बर्ड ब्लॉक–2 संचार उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

कैबिनेट बैठक

उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक गैस पर वैट की दर बीस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। आज सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमण्डल ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले को मंत्रिमंडलीय उपसमिति को सौंपने का फैसला लिया।

आपदाग्रस्त धराली और आसपास के क्षेत्रों में सेब उत्पादकों को राहत देते हुए रॉयल डिलिशियस सेब का मूल्य 51 रुपये और रेड डिलिशियस सेब का मूल्य 45 रुपये प्रति किलो तय किया गया, जिसे संबंधित विभाग खरीदेगा।

संस्कृति विभाग में कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन तीन हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दी गई है।

अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में 100 प्रतिशत लाभ देने का भी फैसला हुआ है, जबकि 125 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।

चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु सीमा 62 वर्ष कर दी गई है। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा।

इसके साथ ही कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए चार नए पद सृजित करने और प्रेस क्लब की इमारत को सूचना विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया।

उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध कब्जों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले का संज्ञान लेते हुए सरकार से जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि विवादित भूमि पर कोई भी निजी व्यक्ति या संस्था किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं दे सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए लगातार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है।

वहीं, प्रमुख वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष आर.के. मिश्र ने कहा कि वन विभाग जल्द ही एक समिति का गठन करेगा, जो वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

गौरतलब है कि यह मामला ऋषिकेश क्षेत्र की लगभग 2 हजार 866 एकड़ वन भूमि से जुड़ा है, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा वन भूमि घोषित किया गया था।

रिज़र्व बैंक

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की समस्या दूर करने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। बैंक ने आगामी दिनों में खुले बाजार परिचालन–ओ.एम.ओ. और विदेशी मुद्रा की खरीद फरोख्त के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक 10 अरब डॉलर की खरीद फरोख्त करेगा। इससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी बढ़ेगी।

बधाणीताल का सौंदर्यीकरण

रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक स्थित बधाणीताल को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सेक्टर वर्ष 2025–26 के अंतर्गत पर्यटन अवस्थापना निर्माण योजना के तहत बधाणीताल के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया।

रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने तीन करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बधाणीताल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ट्रैकिंग मार्गों के विकास, होम–स्टे को बढ़ावा देने तथा आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही मयाली–बधाणीताल सड़क मार्ग को शीघ्र सुचारु किया जाएगा।

पासपोर्ट सेवा केंद्र

पिथौरागढ़ जिले में जल्द ही बहुप्रतीक्षित पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून से आए वरिष्ठ अधिकारियों तजेंद्र सिंह बिष्ट और डी.एस. राणा ने केंद्र के लिए प्रस्तावित कक्षों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद तैयार की गई संयुक्त रिपोर्ट केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र की औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी।

अवैध निर्माण

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण– एमडीडीए का अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में प्राधिकरण ने शिमला बाईपास रोड, एसआर पेट्रोल पंप के समीप, नया गांव, देहरादून में किए जा रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील करते हुए संबंधित को नोटिस जारी किया है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि जांच में यह निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति तथा प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके अलावा रतनपुर, शिमला बाईपास रोड, देहरादून में किए गए एक अन्य अवैध व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया है।

उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ ही यातायात, पर्यावरण और जनसुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा लगातार निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की जा रही है।